बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 145 ● नई दिल्ली ● सोमवार 23 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

हवाई यात्रा लग्जरी नहीं...घरेलू उड़ानों के किराए पर लगी कैपिंग हटाने के फैसले पर केजरीवाल ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हवाई किराए पर लगी कैपिंग हटाने के फैसले को लेकर चिंता जताई है। केजरीवाल ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि, मध्य वर्ग के लिए हवाई यात्रा अब पहुंच से बाहर होती जा रही है। मोदी सरकार ने घरेलू हवाई किराए पर लगी कैपिंग हटा दी है, जिससे टिकटों की कीमतों में तेज वृद्धि हो सकती है। उन्होंने लिखा कि, सरकार को इसकी बजाय हवाई किराए को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि अब हवाई यात्रा किसी लग्जरी की नहीं, बल्कि मध्य वर्ग के लिए जरूरी हो गई है।

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

प्रकाश उइके बने भारतीय आदिमजाति सेवक संघ के नए अध्यक्ष

आदिवासियों के लिए बनाएंगे लीगल सेल, आदिवासियों में जागी एक नई उम्मीद

दिल्ली (सहिल गौड़)भारतीय आदिम जाति सेवक संघ (ब्रह्मस्) अब एक नए स्वरूप और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, दिल्ली में भारतीय आदमजाति सेवक संघ की बैठक में सर्वसम्मति से पुर्व न्यायाधीश व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्य परामर्शदाता प्रकाश कुमार उइके को भारतीय आदमजाति सेवक संघ का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया, आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए समर्पित संगठन भारतीय अदमजाति सेवक संघ का गौरवशाली विरासत के साथ अब एक नए नेतृत्व के तहत कार्य करेगा। बैठक में संघ में कुछ नए सदस्यों को भी मनोनीत किया, अब वर्तमान कार्यकारणी में उपाध्यक्ष ड्ड आर एम कुबेरप्पा, महासचिव अजय कुमार चौबे, कुंवर जितेन्द्र नरसिंह राणा, कोषाध्यक्ष श्रीमती एला बैन देसाई, सचिव पद पर राजेश मालविया, सुरेन्द्र कुमार चौहान, प्रदीप महान्ती, कार्यकारणी सदस्य भुवनेश शर्मा, सदस्य जय प्रकाश गुप्ता,मुकन्द बापट, कुंवर जितेन्द्र नरसिंह व धानका समाज के राजेन्द्र खर्रा, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मुन मुन भाई मिश्रा को मनोनीत किया गया,

इस अवसर पर महासचिव अजय कुमार चौबे ने भारतीय आदिमजाति सेवक संघ के इतिहास पर नजर डालते हुए बताया कि इसकी स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई टक्कर बापा (अमृतलाल ठक्कर) द्वारा ड्ड राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में आदिवासियो के उत्थान के लिए की गई। जो बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति बने,इस संगठन का नेतृत्व समय-समय पर देश के महान और प्रतिष्ठित व्यक्तिवों ने किया गया,सभी महान नेताओं ने संगठन को मजबूत आधार प्रदान किया,आज इसकी शाखाएं देशभर फैली है।

प्रकाश कुमार उइके ने इसे अपने लिए नई चुनौती मानते हुए कहा कि आदिवासियों समूदाय आज भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, तभी देश की मुख्य धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा, प्रकाश कुमार उइके के आदिवासियों के लिए एक लीगल सेल बनाने पर जोर दिया, उन्होंने बताया आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जल्द ही एक लीगल सेल का गठन किया जाएगा जो देश के सभी हिस्सों में लोगों को जागरूक कर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर संघर्ष करने के लिए तैयार करेगा।

इस अवसर पर देश के सभी प्रांतों से आदिवासी समुदाय के प्रमुख लोग उपस्थित थे, सभी ने नए अध्यक्ष प्रकाश कुमार उइके को अपना समर्थन करते हुए बताया कि आने वाले समय में भारतीय आदमजाति सेवक संघ का नया स्वरूप देखने को मिलेगा।

बैठक को सुचारू रूप चलाने व व्यवस्था में भारतीय आदमजाति सेवक संघ के कार्यालय सचिव रविकांत झा, अनिल शर्मा, परदेसी राणा सहित सभी कर्मचारियों ने अहम् भूमिका निभाई।

भारत आखिर कैसे देगा जवाब?

चीन ने तिब्बत के यारलुंग सांगपो नदी पर जिस विशाल जलविद्युत परियोजना की शुरुआत की है, उसने एशिया की भू-राजनीति में हलचल नहीं बल्कि भूकंप ला दिया है। यह कोई साधारण बांध नहीं, बल्कि पानी के जरिये ताकत हासिल करने की खुली रणनीति है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी मार सीधे भारत और बांग्लादेश जैसे निचले देशों पर पड़ने वाली है। इस साल की शुरुआत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने नववर्ष संबोधन में जब इस परियोजना का ऐलान किया तो दुनिया को साफ संदेश मिला कि चीन अब न तो पर्यावरण की चिंता करेगा और न ही पड़ोसी देशों की। करीब 167 अरब डॉलर की लागत से बन रही यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत योजना बताई जा रही है जिसकी क्षमता 67 से 80 गीगावाट तक आंकी जा रही है। तुलना करें तो यह थ्री गॉर्जेस बांध से भी लगभग तीन गुना बड़ी हो सकती है। यह वही नदी है जो भारत में सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र बनती है और आगे बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती है। अकेले ब्रह्मपुत्र घाटी में भारत के करीब तेरह करोड़ लोगों की आजीविका इस नदी पर निर्भर है जबकि बांग्लादेश में यह संख्या करोड़ों में है। यानी यह परियोजना सीधे करोड़ों जिंदगियों पर असर डालने वाली है। चीन इस परियोजना को हरित ऊर्जा का नाम दे रहा है, लेकिन असल खेल कहीं ज्यादा गहरा है। नदी के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण का मतलब है नीचे बहने वाले पानी पर नियंत्रण। और यही वह बिंदु है जहां यह परियोजना एक रणनीतिक हथियार बन जाती है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि यदि चीन चाहे तो सूखे के समय पानी रोक सकता है और तनाव के समय अचानक छोड़ सकता है। इससे बाढ़ जैसी तबाही पैदा हो सकती है। यही वजह है कि भारत के पूर्वोत्तर में इसे वाटर बम कहा जा रहा है। लोवी संस्थान की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि तिब्बत के पठार पर चीन का बढ़ता जल नियंत्रण भारत की अर्थव्यवस्था पर गला घोंटने वाला दबाव बना सकता है। यह केवल जल संकट नहीं बल्कि खाद्य संकट और ऊर्जा संकट को भी जन्म दे सकता है। जिस इलाके में यह परियोजना बन रही है वह भूगर्भीय दृष्टि से बेहद अस्थिर है। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में गिना जाता है और यहां भूकंप तथा भूस्खलन आम बात है। ऐसे में इतनी बड़ी संरचना बनाना सीधे आपदा को निमंत्रण देना है। यदि किसी भी कारण से बांध को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है। ब्रह्मपुत्र की तेज धारा और विशाल जल प्रवाह इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। इसके अलावा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा। अनुमान है कि ब्रह्मपुत्र हर साल लगभग सात सौ मिलियन टन गाद लेकर आती है जो असम और बांग्लादेश की जमीन को उपजाऊ बनाती है। यदि यह प्रवाह बाधित हुआ तो खेती पर सीधा असर पड़ेगा। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता पारदर्शिता को लेकर है। न तो पर्यावरणीय रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और न ही स्थानीय लोगों से कोई राय ली गई है। तिब्बती समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इसे चीन का दोहरा रवैया बताया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि चीन जब अपने हित में होता है तो अंतरराष्ट्रीय नियमों की बात करता है और जब नहीं होता तो उन्हें कुचल देता है। चीन की इस चाल के जवाब में भारत ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। भारत पूर्वोत्तर में 208 बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिसकी कुल क्षमता 75 गीगावाट से ज्यादा होगी। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपर सियांग है जिसकी ऊंचाई लगभग तीन सौ मीटर और क्षमता ग्यारह गीगावाट होगी। इसका मकसद केवल बिजली बनाना नहीं बल्कि चीन के जल नियंत्रण के खतरे को संतुलित करना है। भारत की योजना है कि वर्ष 2047 तक ब्रह्मपुत्र बेसिन से छिहत्तर गीगावाट से अधिक बिजली पैदा की जाए। यानी यह साफ है कि यह अब ऊर्जा की दौड़ नहीं बल्कि रणनीतिक टकराव बन चुका है। अब यह संघर्ष केवल नदी तक सीमित नहीं रहा। जलविद्युत परियोजनाएं अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। चीन अपने बांधों को स्मार्ट ऊर्जा तंत्र से जोड़ रहा है जबकि भारत भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और डेटा विश्लेषण पर काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जो देश पानी को नियंत्रित करेगा वही ऊर्जा और डेटा दोनों पर नियंत्रण हासिल करेगा। यानी भविष्य की ताकत अब पानी और तकनीक के गठजोड़ में छिपी है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत और चीन के बीच कोई औपचारिक जल समझौता नहीं है। यानी कोई बाध्यता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अतीत में चीन ने साल 2000 में आई बाढ़ के दौरान जरूरी आंकड़े साझा नहीं किए थे जिससे भारी नुकसान हुआ था। इससे भरोसे की कमी और गहरी हो गई है। आज हिमालय केवल सीमाओं का नहीं बल्कि पानी और ऊर्जा का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। चीन अपनी तकनीकी और आर्थिक ताकत के बल पर बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत जवाबी संतुलन बनाने में जुटा है। बांग्लादेश के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि वह पूरी तरह इस नदी पर निर्भर है। यदि सूखे के समय पानी घटा तो वहां खाद्य संकट गहरा सकता है। बहरहाल, चीन का यह मेगा बांध विकास का प्रतीक कम और वर्चस्व की रणनीति ज्यादा लगता है। यह परियोजना आने वाले समय में एशिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। अब यह केवल पर्यावरण या ऊर्जा का मुद्दा नहीं रहा। यह सत्ता, संसाधन और भविष्य की दिशा तय करने वाली जंग बन चुका है। ब्रह्मपुत्र की हर बूंद अब सिर्फ पानी नहीं रही, बल्कि वह आने वाले समय की शक्ति और संघर्ष की कहानी लिख रही है।

ममता-शुभेंदु अधिकारी का रण

पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाली लड़ाई पर टिकी हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी भाजपा की तरफ से चुनौती दे रहे हैं। पांच साल पहले, अधिकारी ने नंदीग्राम में बनर्जी को हरा दिया था, जिससे उन्हें अपनी पुरानी सीट भवानीपुर लौटना पड़ा था। चुनाव के तुरंत बाद शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अपनी बॉस के लिए यह सीट खाली कर दी थी और बनर्जी ने लगभग 60,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी।

हालांकि, इस बार उनके लिए यह इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि भवानीपुर की बदलती आबादी बनर्जी के मुख्य चुनावी मुद्दे बंगाली राष्ट्रवाद से टकरा सकती है। भवानीपुर में मिली-जुली आबादी है, जिसमें से कम से कम 40 प्रतिशत लोग गैर-बंगाली हैं। ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं और इस सीट पर दुकानदार, व्यापारी और छोटे कारोबारी के तौर पर व्यापारिक केंद्र चलाते हैं। इस तबके के बीच भाजपा का असर लगातार बढ़ रहा है। कागजों पर देखें तो, इस बार बनर्जी के लिए यह एक मुश्किल लड़ाई साबित हो सकती है, खासकर अधिकारी जैसे जोशीले नेता के खिलाफ, जो इस सीट पर अपनी साख मजबूत करने के लिए अपनी नंदीग्राम वाली जीत का झंडा लहरा रहे हैं। हालांकि अधिकारी नंदीग्राम से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें भवानीपुर से भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे अधिकारी बनर्जी को इसी सीट पर उलझाए रखेंगे और बंगाल के बाकी हिस्सों में उनके चुनाव प्रचार में रुकावट डालेंगे। बनर्जी टीएमसी की स्टार प्रचारक हैं और चुनाव के दौरान हर एक सीट पर जाने की कोशिश करती हैं। भाजपा की रणनीति चाहे जो भी हो, पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफर में भवानीपुर से ग्यारह बार जीत हासिल की है। उन्हें इस सीट का चप्पा-चप्पा पता है और शायद हर एक वोटर का नाम भी याद है। दूसरी तरफ, अधिकारी इस सीट के लिए बाहरी हैं। उन्हें सबसे पहले इस इलाके को समझना होगा। यह एक बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। असम में भाजपा को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि, उन्हें दिसपुर से भाजपा उम्मीदवार बनाने के फैसले को लेकर पार्टी की स्थानीय इकाई में कुछ तनाव नजर आ रहा है। इस सीट के लिए पार्टी के दावेदार अतुल बोरा नाराज हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने या कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की धमकी दी है। किसी भी तरह से, यह भाजपा के लिए चिंता की बात है क्योंकि इससे बोरदोलोई के वोटों में सेंध लगने की संभावना है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, बोरदोलोई को पार्टी में शामिल किए जाने से खुश नहीं हैं।

यह आलाकमान का आदेश था, क्योंकि पार्टी के मुख्य चुनाव रणनीतिकार दलबदलुओं का स्वागत करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सरमा के वफादार इस रणनीति से हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस से दलबदलुओं की मदद मिले या न मिले, पार्टी वैसे भी राज्य में जीत की मजबूत स्थिति में है। भाजपा शासित असम में कांग्रेस अपनी संभावनाओं को लेकर इतनी अनिश्चित है कि राज्य के लिए उसके चुनाव प्रबंधक, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सलाह के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का सहारा लिया। शिवकुमार ने हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद की एक बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि असम विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति (ब्लूप्रिंट) बनाने के लिए उन्होंने एक एआई प्लेटफॉर्म की मदद ली थी। इसके बाद उन्होंने यह दावा भी किया कि एआई ने सुझाव दिया है कि पार्टी असम में 'कर्नाटक मॉडल' का इस्तेमाल करे। शिवकुमार ने दावा किया कि एआई ने कांग्रेस द्वारा पिछले राज्य चुनाव के दौरान घोषित पांच कल्याणकारी गारंटियों को असम के लिए एक सफल रणनीति माना है; इन्हीं गारंटियों की बदौलत पार्टी ने भाजपा पर शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने शासन और प्रशासनिक कार्यों के लिए एआई का इस्तेमाल करने का श्रेय अपनी बेटी को दिया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस टूल को चलाना सीखा, तो उन्हें पता चला कि यह राजनीतिक डेटा का भी विश्लेषण कर सकता है। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने असम के लिए सलाह लेने का फैसला किया। शिवकुमार और प्रियंका गांधी असम में कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की देखरेख कर रहे हैं। भाजपा ने अगस्त 2024 में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या की घटना को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल को उजागर करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या पीड़ित डॉक्टर की मां को 24 परगना (उत्तर) जिले की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए; इसी जिले में पीड़ित का परिवार रहता है। यह सुझाव भाजपा के आम कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया है, वे चाहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिसने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की हो। इसके अलावा, हालांकि अब तक पीड़िता की पहचान सभी को पता चल चुकी है, लेकिन जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक उसका नाम लेना 'सब-ज्यूडिस' (अदालती कार्यवाही के अधीन) माना जाएगा, क्योंकि कानून के अनुसार उसके नाम को गोपनीय रखना अनिवार्य है। यदि उसकी मां को चुनाव मैदान में उतारा जाता है, तो पीड़िता का नाम सार्वजनिक हो जाएगा, जिससे एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। भाजपा ने इस क्षेत्र से अपने उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। इस क्षेत्र में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है।

सम्पादकीय...

युद्ध की राजनीति और विश्व समुदाय की चुप्पी- मानवता के समक्ष एक अस्तित्वगत संकट

आज की दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहाँ युद्ध और शांति के बीच का फासला निरंतर सिमटता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा, विस्तारवादी नीतियाँ और क्षेत्रीय संघर्षों ने वैश्विक व्यवस्था को गहरे अस्थिरता के भंवर में धकेल दिया है। ऐसे में यह यक्ष प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मानव सभ्यता पुनः उसी आत्मघाती मार्ग पर अग्रसर है, जिसने पिछली शताब्दी में दो भयावह विश्व-युद्धों का दंश झेला था? कोई भी संवेदनशील व्यक्ति युद्ध का समर्थक नहीं हो सकता। मानवता और प्रकृति से अनुराग रखने वाला मन भली-भांति जानता है कि युद्ध अंततः केवल विनाश का ही पर्याय है। युद्ध की विभीषिका में सबसे पहले और सबसे अधिक आहुति निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की चढ़ती है। इस दृष्टि से युद्ध का विरोध करना केवल एक वैचारिक स्टैंड नहीं, बल्कि मानवता के प्रति एक सर्वोच्च नैतिक जिम्मेदारी है। विडंबना यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थपरक धरातल अक्सर इन नैतिक मूल्यों से कोसों दूर होता है। इतिहास साक्षी है कि शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व, आर्थिक साम्राज्य और सामरिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कमजोर देशों पर युद्ध थोपे हैं। जब-जब ऐसा हुआ है और वैश्विक समुदाय मौन रहा है, तब-तब उस चुप्पी ने अन्याय को न केवल वैधता प्रदान की है, बल्कि हमलावर को और अधिक आक्रामक होने का अवसर भी दिया है। पिछले तीन दशकों के वैश्विक मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हस्तक्षेप की यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। यूगोस्लाविया से लेकर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और वर्तमान में यूक्रेन व सूडान तक- सैन्य हस्तक्षेपों ने समूचे भूगोल को हिंसा और असुरक्षा की स्थायी स्थिति में झोंक दिया है। लाखों का विस्थापन, हजारों निर्दोषों का संहार और सामाजिक ढांचों का पूर्ण विध्वंस इन युद्धों की वास्तविक उपलब्धि रही है। इसी पृष्ठभूमि में पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट वैश्विक नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा है। फलस्तीन का प्रश्न पिछले सात दशकों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और अनसुलझा घाव बना हुआ है। गाज़ा और पश्चिमी तट पर जारी निरंतर हिंसा ने मानवाधिकारों के दावों और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रामाणिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता यह तनाव अब एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को जन्म दे रहा है। यदि यह दावानल फैला, तो इसका प्रभाव भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे, जिससे पूरी दुनिया एक साथ प्रभावित होगी। यही वह क्षण है जब विश्व समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। क्या वैश्विक शक्तियाँ केवल अपने सामरिक हितों के चश्मे से दुनिया को देखेंगी, या वे शांति और न्याय को प्राथमिकता देंगी? यदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं केवल शक्तिशाली देशों की राजनीतिक सुविधा का साधन बनी रहीं, तो उनकी विश्वसनीयता का अंत निश्चित है। आज परमाणु हथियारों की मौजूदगी इस संकट को कयामत के करीब ले जाती है। शीत युद्ध का अनुभव हमें चेतावनी देता है कि सैन्य उन्माद का मार्ग अंततः पूरी सभ्यता को श्मशान में बदल सकता है।

बुर्के को लेकर यूपी वाला मॉडल बंगाल में भी लागू होगा!

गुजरात के संदेसरा बंधु का बैंकों के साथ क्लेम सेटल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के अंत में इसकी मंजूरी दी थी। संदेसरा बंधुओं नितिन और चेतन संदेसरा के साथ जांच एजेंसियों और कर्ज देने वाले बैंकों के बीच सहमति बनी थी कि 5100 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कहा गया है कि इसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मान कर स्वीकार किया जाए और संदेसरा बंधुओं के खिलाफ बैंक घोटाले, धोखाधड़ी या लोन डिफॉल्ट सहित तमाम आपराधिक मामले समाप्त किए जाएं।

समस्या यह है कि संदेसरा बंधु की स्टर्लिंग बायोटेक पर बैंकों का बकाया 19400 करोड़ रुपए के करीब है। हैरानी की बात है कि जो डिफॉल्ट की रकम है उसके एक चौथाई के बराबर रकम को फुल एंड फाइनल मान कर सारे आपराधिक मामले समाप्त किए गए हैं। इसके मुकाबले कर्नाटक के कारोबारी विजय माल्या का मामला देखें। विजय माल्या के खिलाफ 6000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का डिफॉल्ट था। उन्होंने बैंकों से कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। उनकी विमानन कंपनी घाटे में चल रही थी, जिससे वे समय पर कर्ज नहीं चुका सके। गिरफ्तारी के डर से वे भाग गए थे। उसके बाद से वे भगोड़ा कारोबारी हैं और सरकारी जांच एजेंसियां उनसे 14000 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल चुकी हैं। यानी मूल रकम के दोगुने से ज्यादा वसूली हो गई है। लेकिन ब्याज जोड़ कर रकम 20000 करोड़ पहुंचा दी गई है। एक कारोबारी का 19000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज 5000 करोड़ में सेटल हो रहा है और दूसरे का 6000 करोड़ का कर्ज 14000 करोड़ में भी सेटल नहीं हो पा रहा है।

यूपी वाला मॉडल बंगाल में भी लागू होगा

उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में इस मॉडल को लागू किया था लेकिन अब चुनाव आयोग ने वहां से सीख लेकर पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने का फैसला किया है। इस मॉडल के तहत बुर्केवाली महिलाओं की जांच मतदान केंद्र के बाहर भी की जाएगी। ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जांच दो बार या उससे ज्यादा बार भी हो सकती है। आज़म खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में पुलिस ने मतदान केंद्र से बहुत पहले ही बैरिकेड लगा दिए थे और बुर्के वाली महिलाओं की जांच मतदान केंद्र के बाहर ही की जा रही थी। इतनी जगह बैरिकेड लगाए गए थे और इतनी जांच हो रही थी कि बहुत से लोग रास्ते से लौट गए। असल में, नियम यह कहता है कि बुर्केवाली महिला को मतदान केंद्र के भीतर जाकर ही अपना चेहरा दिखाना है। वहीं पर मतदाता सूची में लगी फोटो से उसका मिलान होगा और वोट डालने के लिए उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तय किया है कि मतदान केंद्र के बाहर ही उनकी जांच होगी। सवाल है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नया नियम क्यों बनाया गया? एक ही वजह समझ में आती है कि ऐसी जांच से बचने के लिए बहुत सी महिलाएं मतदान के लिए जाएंगी ही नहीं, जिसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा।

मोदी के साथ ही 'ऐसे संयोग' होते रहते हैं!

ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उनकी तस्वीर लेकर पहुंचता है और भारी भीड़ में भी मोदी उसे देख लेते हैं। बाद में उसे मोदी से मिलवाया जाता है। मोदी के काफिले के आगे एंबुलेंस आ जाने और उसे रास्ता दिए जाने का संयोग भी कई बार हो चुका है। हर स्थान से उनका निजी रिश्ता निकल जाना तो सबसे कॉमन संयोग है। लेकिन यह संयोग भी बहुत बार होता है कि वे राज्यों में चुनाव से ठीक पहले वे जिस दिन आखिरी दौरा करते हैं उसके अगले ही दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देता है। देखिए कैसा संयोग है कि प्रधानमंत्री पिछले एक महीने से तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम के दौरे कर रहे थे। अभी बीते 14 और 15 मार्च को उनका असम और बंगाल का दौरा होना था, लेकिन उसे एक दिन पीछे खिसका दिया गया। वे 13 और 14 को असम व बंगाल में रहे, जहां हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जम कर हमला किया। वे 14 को वहां से लौटे और 15 मार्च को चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। यह राज तो राज ही रहेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले बनता है और आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में तय होती है या आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तय होती है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम उसके हिसाब से बनता है। लेकिन संयोग दिलचस्प है।

केरल के कांग्रेस सांसदों की विधानसभा में जाने की चाह

केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को अपनी एक विचित्र अंदरूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव की घोषणा हो गई है और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी शुरू कर दी है लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के कई सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के करीब आधा दर्जन सांसद विधानसभा चुनाव टिकट चाहते हैं। वे अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए टिकट चाहते हैं। असल में पिछले दो चुनाव से केरल में कांग्रेस के लगभग सभी लोकसभा उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं लेकिन दिल्ली में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। दूसरी ओर इस बार कांग्रेस के ज्यादातर नेता मान रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दो बार से लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा चुनाव जीत रहा है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 10 साल की एंटी इन्कम्बेंसी की वजह से भी कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि वाम मोर्चा हारेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसे में विधायक रहने पर राज्य सरकार में मंत्री बनने की संभावना रहेगी। इसीलिए कई सांसदों पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से इस बारे में बात की। हालांकि राहुल गांधी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सांसद को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। सो, वेणुगोपाल कुछ नहीं कर पाएंगे।

अमृतसर में हारने वालों को बड़ा फायदा

यह कमाल का संयोग है कि पिछले 12 साल में भाजपा के टिकट पर जो भी नेता अमृतसर लोकसभा सीट से लड़ा, वह चुनाव हारा लेकिन हारने के बाद उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक के बाद एक तीन नेताओं के साथ यह संयोग हुआ है। ताजा संयोग तरनजीत सिंह संधु का है, जिन्हें दिल्ली का उप राज्यपाल बनाया गया है। वे 2024 में अमृतसर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला से चुनाव हार गए थे। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत संधु हारने के बाद से बियाबान में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बना कर उनका पुनर्वास किया गया है। उससे पहले 2019 में अमृतसर से लोकसभा चुनाव हरदीप सिंह पुरी लड़े थे। उन्हें भी कांग्रेस के औजला ने हरा दिया था और उसके बावजूद पुरी केंद्र में मंत्री बने। उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में लाया गया। वे शहरी विकास मंत्री रहे और अभी एपस्टीन फाइल्स को लेकर विवादों में घिर जाने के बावजूद पेट्रोलियम मंत्री बने हुए हैं। उससे भी पहले भाजपा के बड़े नेता अरुण जेटली भी अमृतसर में चुनाव हारे थे। उन्हें कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हराया था। बाद में तो कैप्टन खुद ही भाजपा में चले गए। लेकिन 2014 में अमृतसर सीट पर हारने के बाद अरुण जेटली देश के वित्त और रक्षा मंत्री बने। सो, जेटली से शुरू हुआ सिलसिला पुरी से होते हुए संधु तक जारी है।

आखिर नफरत भरे भाषण पर कब सजग और सक्रिय होंगे हमारे हुक्मरान? यक्ष प्रश्न

नफरत भरे भाषण, किसी भी सभ्य समाज के लिए वैचारिक कैंसर और सामाजिक एड्स के जैसा जानलेवा है, लेकिन दुनियावी तर्ज पर भारतीय लोकतंत्र में भी यह एक बुनियादी राजनीतिक-सामाजिक फैशन बनता प्रतीत हो रहा है। कोढ़ में खाज यह कि बहुमत की भूखी संसद और उसके इशारे पर कुछ कुछ फैसले लेने के आदी बन चुके सुप्रीम कोर्ट ने आजादी के 8वें दशक में भी विवादास्पद बयानबाजियों के खिलाफ कोई कड़ा राष्ट्रवादी स्टैंड नहीं लिया ताकि राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर अनवरत रूप से जारी साम्राज्यवादी वैचारिक हमले की धार कुंद की जा सके! ऐसा इसलिए कि इनकी भी अपनी विवशता है। चूंकि पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले अधिकार संपन्न लोग ब्रितानी नौकरशाही और राजशाही के इशारे पर बने भारतीय संविधान को मानने को अभिशप्त हैं और अपनी व्यावहारिक और मौलिक सोच को ताले पर रख चुके हैं, इसलिए हर जनतांत्रिक बीमारी लाइलाज हो चुकी है और भारत माता अपनी ही संतानों को निरंतर मुखाग्नि देते देते थककर बूढ़ी हो चली है। राष्ट्रीय दुर्भाग्य यह कि पहले मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजी नौकरशाहों ने भारत को जातीय, साम्प्रदायिक, भाषाई-क्षेत्र और लिंग के लिहाज से बांटकर निरंतर कमजोर रखने की जो साजिश रची, उसे अंग्रेजों के लाभुक इशारों पर चलने वाले भारत के आजादी कालीन नेताओं ने बहुमत प्राप्ति का लोकतांत्रिक आधार बना दिया। पहले अखंड भारत को खंडित किया और फिर जाति-धर्म-भाषा की तुष्टिकरण वाले अंग्रेजी कानूनों को हूबहू स्वीकार कर लिया। इससे सामाजिक विखण्ड की प्रक्रिया तेज हुई। चौंकाने वाली बात तो यह कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए समाजवादियों और राष्ट्रवादियों ने भी जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र से जुड़े जनभावनाओं को भड़काया और बहुमत पाकर सत्ता हथियाया। लेकिन भारतीयों की नीतिगत एकजुटता की बात मील का पत्थर बनकर रह गई। मतलबी सरकारें बदलती रहीं, भारत माता की आत्मा पर अनगिनत प्रहार जारी हैं, लेकिन हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट प्रबुद्ध और सुसंस्कृत भारत के निर्माण की जगह यूरोपीय और अरबी कलह को भारत पर थोपने की मूर्खता प्रदर्शित कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आजाद भारत में गरीबी और अपराध को जातीय चश्मे से देखा जाता है, सवर्ण यानी सामान्य जाती विरोधी कानून बनाये जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय का जिक्र करते हुए वर्तमान और भविष्य के सवर्ण विरोधी सामाजिक अन्याय किये जाने के निकृष्ट जनतांत्रिक विचारों पर मोहर लगाता है। खासकर भारतीय संविधान से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद (14, 15, 19, 21, SC/ST Act) की तर्क संभाव्यता, आदि) को भी विस्तार से देखने और इनपर पुनर्विचार की जरूरत है। अन्यथा, देर सबेर सामान्य जातियों के बीच भी संसद और सुप्रीम कोर्ट का अप्रासंगिक होना तय है। यक्ष प्रश्न है कि आखिर बहुमत की राजनीति के लिए समाज को कब तक झुलसाया जाएगा, क्योंकि जब सहिष्णुता के विचार बदलेंगे तो व्यवस्था बदलते देर नहीं लगेगी! चूंकि प्रभावित पक्षों के लिए भारतीय संविधान का पक्षपाती दृष्टिकोण एक ऐसा मटमैला पक्ष है, जो जाति, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि में वैधानिक विभेद रखता है और उसे सामान्य जातियों के खिलाफ ऐतिहासिक सामाजिक अत्याचार का प्रतिफल करार देता है। हैरत की बात है कि संविधान जिन लोगों को कानूनी संरक्षण देता है, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक उत्पातों पर से भी प्रशासन अपनी आंखें फेर लेता है, यह जमीनी हकीकत है, इसलिए कतिपय सवाल लाजिमी है। बहरहाल, नफरती भाषण सम्बन्धी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड व्यावहारिक है, और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी संतुलित और सही माना जा सकता है, लेकिन यह बिना विवाद के नहीं है–विशेषकर जातिगत भावनाओं के मामले में। सवाल है कि नफरत भरे भाषण सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था? तो जवाब होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण को अलग से जाति आधारित दंडनीय अपराध घोषित करने की भी याचिका पर विशेष निर्णय देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने स्पष्ट कहा कि केवल ब्राह्मण ही क्यों, किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण स्वीकार्य नहीं है, यानी एक विशेष जाति को अलग सा हेट स्पीच खंड के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। लिहाजा, नेताओं को भी इसी भावना से सख्त कानून बनाना चाहिए। सवाल है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंड तर्कसंगत है? तो जवाब होगा कि भारतीय संविधान और फिलहाल लागू कानून (जैसे दंड संहिता की धाराएँ, आईटी एक्ट, निर्वाचन कानून, आदि) में दरी, भड़काऊ भाषण और जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ पहले से ही दंड का प्रावधान है; लिहाजा, कोर्ट ने इन्हीं तंत्रों को इस्तेमाल करने पर जोर दिया, बजाय एक नई जाति विशेष श्रेणी बनाने के। मसलन, न्यायपालिका का यह तर्क रहा कि अगर हेट स्पीच को रोकना है तो वह समुदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी समुदायों के लिए एक समान और संवैधानिक ढांचे में होना चाहिए, अन्यथा यह न्याय की बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा। जहां तक आपत्तियों और चिंताएँ की बात है तो ब्राह्मण समुदाय के कुछ तबकों का तर्क है कि आज की राजनीतिक और जन चेतना में ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा का एक विशेष और संगठित स्वर बना है, इसलिए उसे अलग से चिह्नित कर रोकने की जरूरत है; जबकि कोर्ट का रुख उनके अनुभव को सामान्य मानकर छोटा करने जैसा लगता है। इसके उलट, दूसरे तरफ से यह डर भी जताया जाता है कि अगर एक जाति को विशेष तौर पर नफरती भाषण के खिलाफ संरक्षित श्रेणी में रखा जाए, तो इसे राजनीतिक रूप से हथियार बनाया जा सकता है और अन्य पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदायों के हेट स्पीच विरोधी बचाव को नरम करने का तर्क भी बन सकता है। संक्षेप में यदि इस स्टैंड पर मूल्यांकन किया जाए तो सैद्धांतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड प्राकृतिक न्याय, समानता और दुमावदार राजनीतिक जातिगत हथियारबंदी से बचाव के लिए उचित और संयमित लगता है। हालांकि, व्यावहारिक तौर पर यह यह भी दिखाता है कि नफरती भाषण को रोकना सिर्फ एक जाति की शिकायत से उठकर इस तरह के घृणा विरोधी कानूनों की दृढ़ और निष्पक्ष अमलीकरण तक जाना चाहिए, चाहे निशाना कौन सा समुदाय हो। कहना न होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समुदायों (खासकर धार्मिक और जातीय) के खिलाफ हेट स्पीच पर लगातार एक ही मूल सिद्धांत बनाए रखा है- धर्म/जाति के आधार पर घृणा फैलाने वाला भाषण अस्वीकार्य है, लेकिन इसका नियंत्रण समान रूप से लागू कानूनों से होना चाहिए, न कि हर समुदाय के लिए अलग अलग राजनीतिक कानूनी व्यवस्था बनाकर। मुसलमान समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच- 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और कई राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण देते हैं या भड़काऊ रैलियाँ करते हैं। इस आदेश का मुख्य तर्क था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा को बढ़ाता है, इसलिए पुलिस और प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत FIR दर्ज करना और जरूरी धाराएँ लगाना चाहिए, उन्हें आम सियासी भाषण की छवि में नहीं ढकना चाहिए।

अलग अलग समुदायों के लिए समान संरक्षण का सिद्धांत- एक लंबित और बहु दायर लिटिगेशन में कोर्ट ने जोर दिया है कि हेट स्पीच रोकने के लिए न्यायपालिका हर छोटी घटना पर मौन सुनवाई नहीं कर सकती, बल्कि यह राज्य/पुलिस का काम है; लेकिन यह भी कहा है कि धर्म या जाति के आधार पर नफरत फैलाने वाला भाषण भारत की धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। इस मामले में कोर्ट का तर्क रहा है कि अगर हेट स्पीच को रोकना है, तो वह एक एक जाति/धर्म के लिए अलग याचिका देकर नहीं, बल्कि सभी समुदायों के लिए एक ही मानक (IPC, चुनाव कानून, आईटी एक्ट आदि) के तहत किया जाना चाहिए; यानी ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, आदिवासी–सभी एक समान ढांचे में संरक्षित हों। राज्य स्तरीय और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मामले-2023 के कुछ आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों (जैसे असम, उत्तर पूर्वी राज्य) को निर्देश दिए कि वे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करें, चाहे भाषण राज्य मंत्रियों या

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्दन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक जमकर बरसेंगे बादल, 19 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए व्यापक अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ और कई चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से मौसम में यह बड़ा बदलाव आया है, जिससे पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, मध्य और कुछ दक्षिणी राज्यों में असामान्य मौसमी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 24 मार्च के आसपास अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इन इलाकों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी दी है, जो अगले 5 दिनों तक जारी रह सकती है।

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट

21 से 24 मार्च तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक बारिश की उम्मीद है। 21 मार्च को अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल में हवाओं की रफ्तार 80 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि ओडिशा में 70 किमी/घंटा

की तेज हवाएं और ओलावृष्टि की आशंका है।

पूर्वी राज्यों में तूफानी मौसम की तैयारी

पूर्वी राज्यों में मौसम और तीव्र होने वाला है। बिहार में 21 मार्च को भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिखरी हुई बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में थंडरस्क्वॉल (50-60 किमी/घंटा, कभी-कभी 70 किमी/घंटा तक) और ओलावृष्टि भी संभव है।

मध्य और पूर्वी भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं, गरज-चमक और ओलावृष्टि का खतरा है। विदर्भ में 24 मार्च को अलग-अलग जगहों पर बारिश और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) चल सकती हैं।

दक्षिणी राज्यों में उमस के साथ बारिश

दक्षिणी राज्य और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिखरी हुई बारिश होने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 21 से 24 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक संभव है।

हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट

23 मार्च को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है।

आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने, पानी के निकट न जाने, बिजली गिरने से बचने और तेज हवाओं में बाहर न निकलने की सलाह दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके मद्देनजर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को नोएडा पहुंचे। मुख्यमंत्री दोपहर में हेलीकॉप्टर से जेवर स्थित हवाई अड्डा पहुंचे और करीब डेढ़ घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक कर उद्घाटन समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस, यमुना प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारियां की थीं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हवाई मार्ग से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। इस बैठक में अधिकारियों ने समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा योजना, जनसभा में आने वाले लोगों की संभावित संख्या और बैठने की व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह भी गौतमबुद्ध नगर पहुंचे। उन्होंने हवाई अड्डा परिसर और जनसभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसभा के लिए पार्किंग व्यवस्था का सुव्यवस्थित मानचित्र तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा, प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्रिस्टोफ श्रेलमैन और सीओओ किरण जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत, 24 को पेश किया जाएगा सालाना बजट

नई दिल्ली । विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि इस बार का सत्र परंपरा और तकनीक से चलेगा। 23 से 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 24 मार्च को दिल्ली का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। शनिवार को अध्यक्ष ने आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र (बजट सत्र) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी सदस्यों से कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखना और सार्थक चर्चा करना सबकी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष ने सदन के भीतर व्यवस्थाओं, सुरक्षा और प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया, ताकि सोमवार को कार्यवाही बिना किसी बाधा के चले। इस बार तकनीक के इस्तेमाल पर खास जोर है। सभी विधायकों की मेजों पर टैबलेट लगाए गए हैं ताकि उन्हें कार्यवाही और जरूरी दस्तावेज रियल-टाइम में मिल सकेंगे। पहली बार सदन की शुरुआत वंदे मातरम के पूर्ण गायन से होगी। इस दौरान सदन में लगी स्क्रीन पर गीत की पंक्तियां भी दिखाई जाएंगी।

विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि इस बार का सत्र परंपरा और तकनीक से चलेगा।

विधान साथी नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च हो गया है, सोमवार को विधायक इसके जरिये विधेयकों, कानून और नीतियों से जुड़ी जानकारी और विश्लेषण तुरंत ले सकेंगे। इससे विधायी कामकाज में तेजी और स्पष्टता आने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक, इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर खास ध्यान रहेगा। लैंडफिल साइटों पर जमा कूड़े को हटाने के लिए भी ज्यादा फंड रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार का बजट दिल्ली के विकास को ध्यान में रखते हुए संतुलित और समावेशी होगा।

जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा पाई-पाई का हिसाब

नई दिल्ली । देश की जेलों में कैदियों की नारकीय स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 18 मई तक अपनी जेलों का ब्यौरा पेश करें, यानी अदालत ने सभी राज्यों से पाई-पाई का हिसाब मांग लिया है। शीर्ष अदालत ने साफ-साफ कहा है कि अब पुराने आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। राज्यों को 1 मार्च 2026 तक की स्थिति के आधार पर यह बताना होगा कि उनकी जेलों में कुल कितने कैदी हैं। इतना ही नहीं, राज्यों को यह भी बताना होगा कि जेलों में कितने कैदी रह सकते हैं और अभी कितने कैदियों को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से केवल संख्या नहीं पूछी है, बल्कि यह भी पूछा है कि जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं? अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जेल-वार डेटा मांगा है। इससे यह पता चलेगा कि किस जेल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि राज्य अपनी रिपोर्ट में बताएं कि महिला कैदियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं कैसी हैं? इतना ही नहीं, कैदी मां के साथ जेल में रहने को मजबूर बच्चों के भविष्य और शिक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अदालत का कहना है कि इन बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जेलों में बढ़ते अपराध के पीछे अक्सर सुरक्षाकर्मियों की कमी एक बड़ा कारण होती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जेल स्टाफ की संख्या और वर्तमान में खाली पड़े पदों का ब्यौरा भी मांगा है। राज्यों को यह भी बताना होगा कि इन रिक्तियों को भरने के लिए वे क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र गौरव अग्रवाल ने पीठ को बताया कि वर्तमान में शीर्ष अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े 2023 के हैं।

उन्होंने कहा कि न्याय के लिए ताजा डेटा का होना अनिवार्य है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिवों को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि अब इस मामले में 26 मई को अगली सुनवाई होगी। तब तक कोर्ट की रजिस्ट्री इन सभी हलफनामे को न्याय मित्र को सौंपेगी, जो इस डेटा का विश्लेषण कर एक विस्तृत नोट तैयार करेंगे।

कांग्रेस ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दीं, राहुल गांधी ने राज्य को ज्ञान-पुंज बताया

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने रविवार को बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और राहुल गांधी ने इस राय को भारत का ज्ञान-पुंज बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बिहार भारत का ज्ञान-पुंज और हमारा गौरव है- जिसने अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति से हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा, बिहार दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार को लोकतंत्र की पावन धरा और ज्ञान-परंपरा व सभ्यता का प्रतीक बताया। बिहार भारत का ज्ञान-पुंज और हमारा गौरव है - जिसने अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति से हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, इसी भूमि से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध देशवासियों की आवाज को एक नयी दिशा दी थी। उन्होंने कहा, बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खरगे ने कहा, हमारी कामना है कि आप सभी राष्ट्र की प्रगति और विकास में निरंतर अपना अमूल्य योगदान देते रहें। बिहार दिवस 22 मार्च, 1912 को राय के गठन की याद में मनाया जाता है, जब अंग्रेजों ने बंगाल से अलग करके बिहार राय की स्थापना की थी।

वैलेंटाइन डे पर दोस्ती जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में एक आरोपित की नियमित जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वैलेंटाइन-डे पर किसी लड़की का किसी लड़के से दोस्ती करना, उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं देता है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि यहां तक कि लड़की की मांग में उसकी सहमति के बिना सिंदूर लगाना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही यह कानून में निर्धारित अपराध न हो। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने आरोपित वसीम अख्तर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने करावल नगर थाने में फरवरी 2025 में प्राथमिकी हुई थीज आरोपित के खिलाफ फरवरी 2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) -की धारा 64(एक) और 137(दो) और पाक्सो अधिनियम की धारा- चार के तहत प्राथमिकी की गई थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका विरोध करते हुए अदालत को बताया था कि 17 साल की लड़की का बयान दर्ज कराया गया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि वह आरोपित को करीब एक साल से

जानती थी। 14 फरवरी 2025 को आरोपित ने उसे बहाने से घर पर बुलाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसके विरोध के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना के बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस को सूचना दी और उसका पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया । वहीं, आरोपित के अधिवक्ता ने तक दिया कि पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा थी और उसने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। यह भी तर्क दिया गया कि यह घटना वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी और इससे एक प्रेम संबंध के पहलू होने का संकेत मिलता है। जबकि जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता और उसके भाई ने ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है और पीड़िता खुद जमानत का विरोध करने के लिए कोर्ट में पेश हुई थी। यह भी कहा कि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 14 जनवरी 2008 थी और उसका नाबालिग होना साबित होता है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता ने भी जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत में मौजूद रही है। उक्त तथ्यों को देखते हुए आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी को मुकदमे के अंतिम चरण में किसी भी पक्ष के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।

पराए पानी पर जी रही राजधानी, उधारी से बुझ रही दिल्ली की प्यास; गर्मी से पहले ही पेयजल संकट

नई दिल्ली। राजधानी में एक के बाद एक करके कुएं, तालाब, झीलें सूखती चली गईं लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। भूजल संरक्षण से कई गुना ज्यादा दोहन हो रहा है। ऐसे में धरती के पेट का पानी लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली कच्चे पानी के लिए सबसे ज्यादा यमुना नदी पर निर्भर है जिस पर पहले से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और हरियाणा की प्यास बुझाने का बोझ है। स्थानीय वर्षाजल का योगदान सीमित है, जबकि भूजल का दोहन नियंत्रित स्तर पर किया जाता है। ऐसे में कच्चे पानी की मात्रा में उतार-चढ़ाव शोधन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है राजधानी के वजीराबाद और चंद्रावल संयंत्रों को यमुना से कच्चा पानी प्राप्त होता है। यमुना से मिलने वाला पानी दिल्ली के कुल पेयजल उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। गंगा का पानी अपर गंगा नहर के माध्यम से दिल्ली लाया जाता है, जिससे सोनिया विहार और भागीरथी संयंत्रों को आपूर्ति होती है। हरियाणा से आने वाली मुनक नहर और दिल्ली सब-ब्रांच नहर के जरिये भी कच्चा पानी राजधानी तक पहुंचता है। भाखड़ा स्टोरेज से मिलने वाला पानी हैदरपुर, द्वारका और नांगलोई संयंत्रों के माध्यम से शोधन के बाद वितरित किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थापित ट्यूबवेल और रैनी वेल से भूजल भी निकाला जाता है, जो कुल आपूर्ति में सहायक भूमिका निभाता है। साफ है कि दिल्ली अपने पेयजल के लिए काफी हद तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। यमुना और गंगा बेसिन से आने वाला पानी ही राजधानी की जलापूर्ति की रीढ़ है। 2024 में सीजीडब्ल्यूबी की तरफ से प्रकाशित भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन 2024 के अनुसार, दिल्ली में रिचार्ज से कई गुना अधिक पानी निकाला जा रहा है, जो भूजल संकट की तरफ इशारा करता है। दिल्ली का भूजल विकास स्तर 91 फीसदी है जो दर्शाता है कि दिल्ली का भूजल स्तर खतरे में है। 41.49 फीसदी क्षेत्र अति-दोहन की श्रेणी में है। पूर्वी दिल्ली में 98, नई दिल्ली में 135 और उत्तर पूर्वी दिल्ली 108 प्रतिशत अति-दोहन की श्रेणी में हैं, जबकि मध्य दिल्ली में 81, दक्षिण दिल्ली में 112 और दक्षिण पश्चिम दिल्ली 94 फीसदी गंभीर श्रेणी में है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में अवैध बोरवेल संचालन को गंभीरता से लिया है। यह मामला वरुण लूथरा की याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि मौर्या एन्क्लेव क्षेत्र में बिना अनुमति के बोरवेल से भूजल दोहन किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों से जवाब मांगा था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड और अन्य अधिकारी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। एनजीटी ने इस लापरवाही पर चिंता जताई और कहा कि बोरवेल की वैधता की ठीक से जांच नहीं की गई। दिल्ली जल बोर्ड ने भरोसा दिया है कि दोबारा जांच कर सच्चाई सामने लाई जाएगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उसे धमकियां मिल रही हैं। अधिकरण ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को सुरक्षा दी जाए। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। यमुना से मिलने वाले पानी की मात्रा पर भी मौसम प्रभाव पड़ता है। नदी में प्रवाह कम होने या हरियाणा से कम पानी छोड़ने की स्थिति में वजीराबाद और चंद्रावल संयंत्रों की क्षमता प्रभावित होती है।

मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता

सीएम- पीएम मिलाकर बतौर हेड ऑफ गवर्नमेंट 8931 दिन पूरे; पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे करने के साथ ही पीएम मोदी ने चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी इससे पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वे ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का सबसे लंबा अनुभव है।

मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री बने

17 सितंबर को जन्मे नरेंद्र मोदी 6 साल की उम्र में ही कांग्रेस की ओर से महागुजरात आंदोलन का हिस्सा बने। फिर 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में बिना विधायक बने ही मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे 2002 में, 2007 में और फिर 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। अपने राजनीतिक सफर के 24 सालों में से पीएम मोदी 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।

पिछले 11 साल से वे देश के प्रधानमंत्री हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे पीएम भी हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों (24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977) का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 22 मार्च 2026 तक बतौर प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी 4318

पूरे कर चुके हैं। हालांकि सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। पीएम मोदी नेहरू के रिकॉर्ड से 1812 दिन पीछे हैं। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2029 के बाद भी पीएम रहना पड़ेगा। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के नाम है। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक रहा। यानी वे लगभग 24 साल 165 दिन सीएम रहे।

उन्होंने सीएम ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था। ज्योति बसु 23 साल सीएम रहे थे। उन्होंने लगातार 5 बार चुनाव जीते और बिना ब्रेक इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे। चामलिंग ने मुख्यमंत्री रहते हुए सिक्किम को भारत का पहला 100फीसदी ऑर्गेनिक राज्य बनाया। राज्य में लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए काम किया।

छत्तीसगढ़ के खल्लारी मंदिर में टूटा रोपवे....16 घायल, 1 मौत

20 फीट नीचे गिरी ट्रॉली, चट्टान से टकराई; नवरात्रि पर दर्शन के लिए पहुंचे थे

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक युवती की मौत हो गई। सभी रविवार (22 मार्च) को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माता के दर्शन करने आए थे। सुबह 10:30 बजे दर्शन कर रोपवे से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक केबल टूट गया। ट्रॉली में सवार श्रद्धालु 20 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरे। ट्रॉली पहाड़ी की चट्टान से टकराई।

हादसे में एक युवती की जान चली गई। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक, पहली ट्रॉली के नीचे गिरने से ऊपर जा रही दूसरी ट्रॉली का भी बैलेंस बिगड़ा। इसमें सवार लोग भी घायल हैं। घायलों में ज्यादातर रायपुर के रहने वाले हैं। महासमुंद कलेक्टर ने कहा है कि रोपवे का केबल कैसे टूटा ये जांच के बाद पता लग सकेगा। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, श्रद्धालु दर्शन करके रोपवे से लौट रहे थे। केबल टूटने के बाद ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। लगभग 20 फीट नीचे पहाड़ी की चट्टान से जा टकराई। इस जोरदार झटके के कारण ट्रॉली में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालु दहशत में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को निजी वाहनों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया।

रिपोर्ट- ईरान से सीजफायर वार्ता करना चाहते हैं ट्रम्प- ईरान की शर्त- पहले मुआवजा दो, आगे हमला नहीं होगा इसकी गारंटी भी चाहिए

वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रम्प की टीम ईरान के साथ सीजफायर पर बात करना चाहते हैं। इस काम में ट्रम्प के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी एक्सियोस न्यूज ने दी है। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है कि पहले जंग रोकी जाए और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिले। दूसरी तरफ, ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि वे अभी ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हैं, खासकर मुआवजे की मांग को। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश मध्यस्थ का रोल निभा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद करे, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद करे। इसके अलावा, ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद करे।

कश्मीरियों ने किया दिल खोलकर दान, बर्तन-नकद से लेकर महिलाओं ने सोना-चांदी भी दिया

जम्मू।

कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने युद्धग्रस्त ईरान के लिए दान एकत्र किया है। इसमें नकद, सोना और तांबे के बर्तन जैसी चीजें शामिल थीं। ईरानी दूतावास ने इस मानवीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया है।

घर-घर जाकर जुटाया दान

ईद समारोह के एक दिन बाद रविवार को घाटी के शिया-बहुल क्षेत्रों में युवाओं ने घर-घर जाकर दान जुटाया। यह दान पश्चिम एशिया में ईरान पर हुए युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए था। रैनवारी निवासी ऐजाज अहमद ने इसे इसाइल के जायोनी शासन और उसके समर्थकों द्वारा थोपा गया अवैध युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि सभ्य दुनिया को ईरान के पीड़ित लोगों को सहायता भेजनी चाहिए।

पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सभी वर्गों के लोगों ने इस दान अभियान में भाग लिया।

महिलाओं ने गहने तक दिए दान

महिलाओं ने विशेष रूप से सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन और अन्य कीमती घरेलू सामान दान किए।

कुछ परिवारों ने पशुधन भी दान किया। बच्चों ने अपनी बचत और जेब खर्च देकर योगदान दिया। यह दान मुख्य रूप से बडगाम और बारामूला में एकत्र किया गया, जहां शियाओं की अच्छी खासी आबादी है। एकत्रित योगदान को ईरानी दूतावास सहित आधिकारिक राहत संगठनों के माध्यम से जरूरतमंदों तक भेजा जाएगा।

ईरान बोला- थैंक्यू इंडिया

ईरानी दूतावास का आभार

ईरानी दूतावास ने एक्स (सोशल मीडिया मंच) पर तस्वीरों के साथ आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि कश्मीर के दयालु लोगों की मानवीय सहायता और हार्दिक एकजुटता को कभी नहीं भुलाया जाएगा। दूतावास ने यह भी कहा, हम आपकी दयालुता और मानवता को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने अपने एक अन्य पोस्ट में भारत को धन्यवाद भी दिया।

दान का उद्देश्य

यह दान ईरान में युद्ध से हुई भारी तबाही के पीड़ितों की मदद के लिए है। युद्ध को इजरायल और उसके समर्थकों द्वारा थोपा गया बताया गया है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों तक सीधे राहत पहुंचाना है। कश्मीर के लोगों ने इस पहल के माध्यम से अपनी एकजुटता और समर्थन प्रदर्शित किया है।

ईरान ने इजराइल पर 4 मिसाइलें दागीं - 300 लोग घायल

तेल अवीव/तेहरान। ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार, घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था। यहां इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान की ओर से यह हमले ट्रम्प की धमकी के बाद बढ़े हैं। दरअसल, ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए लिखा- अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचों पर हमला करेगा।

होर्मुज़ स्ट्रेट पर नरम पड़ा ईरान

यूएस- इजरायल को छोड़ दुनिया के लिए खोला रास्ता

ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा है कि यह जलमार्ग उन सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा जिनका संबंध ईरान के दुश्मनों (अमेरिका और इजरायल) से नहीं है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने 48 घंटे के भीतर रास्ता न खुलने पर ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की चेतावनी दी थी। ईरान ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों के जहाज तेहरान के साथ सुरक्षा तालमेल बिठाकर यहां से गुजर सकते हैं। ईरानी प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है ताकि खाड़ी क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस तनाव की असली वजह इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमले हैं। मौसवी के अनुसार, ईरान अभी भी कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन शांति के लिए बाहरी आक्रामकता का रुकना और आपसी भरोसा कायम होना बेहद जरूरी है। बता दें कि 28 फरवरी से ईरान ने इस रास्ते को बंद कर रखा था, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है।

वैश्विक तेल सप्लाई पर मंडराता खतरा

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की कुल तेल और गैस सप्लाई के लगभग पांचवें हिस्से का मुख्य जरिया है। ईरान ने पहले संकल्प लिया था कि वह अमेरिका और इजरायल तक एक लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देगा। इस तनाव के बीच अमेरिका ने जहाजों को सुरक्षा देने के लिए एक नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकांश नाटो सहयोगियों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है।

सहयोगी देशों का कहना है कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिलहाल, ईरान के इस नए बयान से उन देशों को थोड़ी राहत मिल सकती है जो इस रास्ते पर निर्भर हैं।

केसी त्यागी रालोद में शामिल, जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता, वेस्ट की कई सीटों पर बदलेंगे समीकरण

मेरठ। वरिष्ठ राजनेता किशन चंद (केसी) त्यागी रालोद में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने उन्हें रालोद की सदस्यता दिलाई। नौवीं लोकसभा में हापुड़-गाजियाबाद के सांसद रह चुके केसी त्यागी पिछले 26 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का हिस्सा थे। उनके रालोद में आने से वेस्ट यूपी की कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली जाने के निर्णय के बाद जदयू को अलविदा कहने का फैसला किया। उनका मानना है कि बिहार तक सीमित जदयू में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता के लिए भविष्य में कोई विशेष भूमिका नहीं रह जाती। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और आपातकाल के समय जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे दिग्गजों के साथ काम करने के अनुभव के साथ केसी त्यागी ने पिछले 26 वर्षों में केंद्रीय राजनीति में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उनका रालोद में शामिल होना न केवल उन्हें सक्रिय राजनीति में बनाए रखने का एक प्रयास है, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी एक और पारी खेलने का संकेत भी देता है।

इन सीटों पर पड़ सकता है असर

मोदीनगर, मुरादनगर और सिवालखास जैसी सीटों पर, जहां भाजपा के साथ गठबंधन में रालोद का दावा कई वर्तमान विधायकों और भावी प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ सकता है। यह माना जा रहा है कि केसी त्यागी इन सीटों पर अपने करीबी लोगों को टिकट दिलाने के लिए जोर लगा सकते हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ जाएगी।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

मंत्री अनिल कुमार, पूर्व मंत्री अशोक यादव, सुरेंद्र त्यागी, महासचिव त्रिलोक त्यागी, पूर्व सांसद मुंशीराम पाल, पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, विधायक गुलाम मोहम्मद, अजय कुमार, राष्ट्रीय सचिव सुखबीर सिंह गठीना, बागपत जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर आदि मौजूद रहे।

कतर में हेलीकॉप्टर हादसे में छह लोगों की मौत

दोहा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कतर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर के क्षेत्रीय जल में रविवार तड़के हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। इस बात की पुष्टि कतर के आंतरिक मंत्रालय की। मंत्रालय ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। दुर्घटना के बाद बचाव और खोज अभियान तेज कर दिया गया है। आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि बचाव और खोज अभियान जारी है और अधिकारी अभी एक लापता व्यक्ति को ढूंढने में जुटे हैं। हादसे के बाद तटीय सुरक्षा और रेस्क्यू टीमों ने तेजी से काम शुरू किया, लेकिन समुद्री हालात बचाव कार्य को चुनौती दे रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए बनेगा विशेष समूह

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की अहम बैठक में संकट से निपटने के लिए विशेष समूह बनाने का फैसला लिया गया। इस बैठक में तेल, गैस और उर्वरक की सप्लाई को सुरक्षित रखने पर खास जोर दिया गया। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस यह रहा कि देश में किसी भी तरह की सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, वितरण व्यवस्था सुधारने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई की समीक्षा की गई। सरकार ने संकट से निपटने के लिए विशेष समूह बनाने और वैकल्पिक आयात स्रोत तलाशने का फैसला लिया। सरकार ने भरोसा दिया कि देश में ऊर्जा सप्लाई बाधित नहीं होने दी जाएगी।

अधिकारियों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।

बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए?

आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश।

कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश।

राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर।

मंत्रियों और सचिवों का विशेष समूह बनाने का निर्देश।

तेल, गैस और ऊर्जा सप्लाई को हर हाल में बनाए रखने का फैसला।

खाद्य, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस।

उर्वरकों के पर्याप्त भंडार और खरीफ सीजन की जरूरतों की समीक्षा।

उर्वरक के वैकल्पिक आयात स्रोत तलाशने पर जोर।

पश्चिम एशिया संकट पर सीसीएस की बैठक

- संकट से निपटने के लिए मंत्रियों-सचिवों का विशेष समूह बनेगा।
- तेल, गैस और उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश।
- कोयले का पर्याप्त भंडार, बिजली की दिक्कत नहीं होगी।

ईंधन आपूर्ति के लिए अन्य स्रोत तैयार करने के निर्देश

कोयले के पर्याप्त भंडार से बिजली संकट नहीं होने का आश्वासन।

रसायन, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने का निर्णय।

नए निर्यात बाजार विकसित करने की योजना।

शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार करने का फैसला।

सप्लाई चेन को मजबूत और लॉजिस्टिक्स सुधारने के निर्देश।

वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखने और त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति।

देश की अर्थव्यवस्था पर असर का विस्तृत आकलन करने का निर्णय। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर।

समुद्री मार्गों और वैश्विक सप्लाई रूट्स की सुरक्षा पर ध्यान।

उद्योग और आम लोगों पर असर कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश।

कोयले का पर्याप्त भंडार, बिजली की दिक्कत नहीं होगी

बैठक में पीएम को जानकारी दी गई कि सभी विद्युत संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने से भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। इसी तरह रसायन, फार्मास्युटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा आवश्यक आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। यह भी तय किया गया कि भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में नए निर्यात गंतव्य विकसित किए जाएंगे।

डोभाल और शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे

उच्च स्तरीय बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर, खाद्य, उपभोक्ता मामले मंत्री प्रल्हाद जोशी और नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू भी शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के दो प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी इसमें शिरकत की।

पीएम ने दी सरकार के प्रयासों की जानकारी

बैठक में पीएम मोदी ने देश में ऊर्जा संकट दूर करने के लिए हो सरकार की ओर से हो रहे कूटनीतिक प्रयासों की जानकारी दी जिनमें कई शासनाध्यक्षों से हुई द्विपक्षीय वार्ता भी शामिल है। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों, ईरान, इस्राइल, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। पीएम ने बीते शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति से एक सप्ताह में दूसरी बार बात की और युद्ध के दौरान दूसरे देशों के ऊर्जा भंडारों पर हो रहे हमले को अस्वीकार्य बताया।

होर्मुज और वैश्विक असर पर चिंता?

बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी चिंता जताई गई, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर वैश्विक बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।